भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 426
मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़,1947 (शक) को उत्तरार्थ

मेरी समिति मेरा पटल

†**426. श्री नारायण तातू राणेः**
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री चंदन चौहानः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री अनुराग शर्माः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती माला राज् यलक्ष् मी शाहः
श्री ढुलू महतोः
श्री नव चरण माझीः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री आलोक शर्माः
श्री बिप्लब कुमार देबः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'मेरी समिति मेरा पटल' पहल का उद्देश्य क्या है;

(ख) हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल उत्तर भारत में सहकारी समितियों के कार्य संचालन और जनसंपर्क में कैसे परिवर्तन लाएगा;

(ग) क्या सरकार देश भर की सभी सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए उक्त पोर्टल का विस्तार करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में पहचान, पारदर्शिता और डिजिटल एकीकरण के संदर्भ में, विशेषकर त्रिपुरा राज्य में, कोई ठोस लाभ मिलने की उम्मीद है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): "मेरी समिति मेरा पटल" एक पहल है जिसे क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (RICM), चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से परिकल्पित और प्रारंभ किया गया है । "मेरी समिति – मेरा पटल" का उद्देश्य प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सशक्त और आधुनिक बनाना है, जिसके अंतर्गत उनके प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना, शासन व्यवस्था को सुधारना और उनकी दृश्यता को बढ़ाना शामिल है ।

(ख): यह पहल विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता के लिए पैक्स की डिजिटल प्रोफाइलिंग और केंद्रीकृत, पारदर्शी, रियल टाइम डेटा प्रणाली के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है । इस कार्यान्वयन में क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (RICM), चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (RICM), चंडीगढ़ द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लेह-लद्दाख शामिल हैं ।

(ग): वर्तमान में उक्त पोर्टल का पूरे देश में विस्तार करने की कोई योजना नहीं है ।

(घ): इस पहल के अधीन पैक्स. और MPCS के लिए निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभों की उम्मीद है :

- **पहचान और पारदर्शिता :** प्रत्येक PACS/MPCS की अपेक्षा होती है कि उसकी एक डिजिटल प्रोफ़ाइल हो जो उसके इतिहास**,** सदस्यता**,** प्रदान की गई सेवाओं**,** लाभार्थ योजनाओं तथा शासन संरचना को प्रदर्शित करे।
- **सार्वजनिक दृश्यता:** इस पहल से सार्वजनिक क्षेत्र में पैक्स**/MPCS** की दृश्यता बढ़ने की उम्मीद है **।**
- **रियल टाइम डेटा पारदर्शिता:** इस पहल से रियल टाइम के डेटा तक पहुंच को सक्षम करके पारदर्शिता को बढ़ावा देने की उम्मीद है ।

(ङ**)** त्रिपुरा इस पहल का हिस्सा नहीं है ।

****